



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत-म्यांमार आर्थिक सहयोग का स्वरूप

पप्पु कुमार

भारत एवं म्यांमार एक - दुसरे के साथ नजदीकी एवं सहयोगात्मक संबंध रखते हैं। दो हजार वर्षों के ऐतिहासिक एवं संस्कृति सहयोग तथा दोनों देशों के बीच 1,600 कीमी. के लम्बे सीमा के चलते यह संबंध और मजबूत हुआ है। 1960 के दशक में भारत म्यांमार का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार था जिसमें व्यापार का संतुलन बर्मा के पक्ष में था। क्योंकि भारत, म्यांमार से बड़ी मात्रा में चावल आयात करता था। म्यांमार सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार वर्ष 1980-81 में 12.4 मिलियन अमरीकी डालर का व्यापार 90 के दशक में 328 मिलियन डालर तक पहुँच गया। व्यापार की राशि 2009-10 तक 112 खरब अमरीकी डालर पहुँच गया। मात्र दो वर्षों में दोगुनी वृद्धि दर्ज हो गई। थाईलैंड, सिंगापुर, चीन के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा म्यांमार का व्यापारिक हिस्सेदार है।

द्विपक्षीय व्यापार

भारत द्वारा कृषि एवं जंगल आधारित उत्पाद का म्यांमार से सबसे ज्यादा आयात होता है। म्यांमार, भारत को बिन एवं दल निर्यात करता है। म्यांमार द्वारा भारत को प्राथमिक वस्तुएं एवं उत्पादित वस्तुओं का भी निर्यात होता है। भारत म्यांमार को प्राथमिक तथा अर्धनिर्यात स्टील, स्टील की छड़ें एवं स्टील से बने अन्य उत्पाद, भारत द्वारा निर्यात की जाती है। भारत की दवा कंपनियों ने म्यांमार के 40% बाजार पार कब्जा जमाया है।

द्विपक्षीय व्यापार करीब 1600 कीमी. लम्बे सीमा के आर - पार होता है। वर्ष 2009-10 में यह व्यापार 13.73 मिलियन डालर था जो पिछले वर्ष बढ़कर 9.8 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। सीमा रेखा पर दो व्यापार स्थान निर्धारित किये गये हैं। मोरेह - तमू (1995) जवारवधार-ही (2004) जगहों से व्यापार शुरू हो चुके हैं तीसरी जगह अवाखुंग - लेशी पर हाल में सूती धागे, गाड़ियों के पार्ट - पुर्जे, दवाएँ एवं सोयाबीन भारत की ओर से तथा दालें, सूखी आदि, सुपाड़ी, हल्दी आदि वस्तुएं म्यांमार की से सीमा व्यापार के रूप में विनिमय होती है।

द्विपक्षीय व्यापार में 1980-81 से 2009-10 के बीच 12.4 मिलियन अमरीकी डालर से 1207.56 मिलियन अमरीकी डालर के रूप में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।

भारत म्यांमार से कृषि आधारित उत्पादों, जिससे बिन, दालें एवं जंगलों के उत्पाद शामिल हैं, आयात करते हैं। यह भारत द्वारा आयातित वस्तुओं का 90% भाग है। भारत द्वारा म्यांमार को प्राथमिक एवं अर्धनिर्मित स्टील एवं दवाएँ निर्यात करता है। यागों के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार निर्यात - आयात के निम्नलिखित आँकड़े हैं।

निर्यात भारत के साथ व्यापार (आधिकारिक विनियम दरों पर)

2004 - 05	-	341.40	मिलियन अमरीकी डालर
2005 - 06	-	489.10	मिलियन अमरीकी डालर
2006 - 07	-	733.59	मिलियन अमरीकी डालर
2007 - 08	-	727.85	मिलियन अमरीकी डालर
2008 - 09	-	804.96	मिलियन अमरीकी डालर
2009 - 10	-	1010.56	मिलियन अमरीकी डालर

आयत

2004 – 05	-	83.37	मिलियन अमरीकी डालर
2005 – 06	-	80.37	मिलियन अमरीकी डालर
2006 – 07	-	159.54	मिलियन अमरीकी डालर
2007 – 08	-	173.46	मिलियन अमरीकी डालर
2008 – 09	-	146.18	मिलियन अमरीकी डालर
2009 – 10	-	194.03	मिलियन अमरीकी डालर

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा ऋण के जरिये म्यांमार में निवेश को बढ़ावा देने की लगातार प्रयास तेज किये गये हैं। भारत 13 वाँ सबसे बड़ा निवेशकर्ता है। इनके अनुमानतः 189 मिलियन अमरीकी डालर, म्यांमार में निवेश किया है। यह निवेश पांच परियोजनाओं में किया गया है। भारत का निवेश तेल एवं गैस क्षेत्र से लेकर जलविद्युत एवं रेलवे एवं विद्युत क्षेत्रों में हुआ है। भारत की ओर से बहुउपयोगी कलादान परियोजना पर 120 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश हुआ है। कलादान नदी विकास द्विपक्षीय राजपथ के रूप में तथा रखीने राज्य में सिनवे बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 20 मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के साथ 2121 मोटर्स द्वारा भारी मालवाहनों के निर्माण का प्लॉट लगाया जा रहा है।

उपरोक्त बातों के अलावे, भारत ने म्यांमार में विकास परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया है। इन परियोजनाओं को भारत सरकार की ओर से ऋण एवं आर्थिक सहायता प्रदान किये जा रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने बहुत से उच्च पथों के निर्माण में सहायता करने की इच्छा जहिज की है। तामुकले ओर ही रिडीम पथ के स्तर को उचां उठाने, भारत - म्यांमार- थाईलैंड के बीच उच्च पथ की प्रियोजुआ के अलावे रेलवे के साजो समान संचरण के लिये दूर संवेदी उपकरणों की आपूर्ति की परियोजनाए भी शामिल है।²

आपसी यात्राएं

संस्थागत स्तर पर भारतीय उद्योग महासंघ वाणिज्य महासंघ के बीच फरवरी, 2000 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। इसी तरह भारतीय उद्योग महासंघ एवं म्यांमार कम्प्युटर संघ के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। वर्ष 2004 के फरवरी महीने में योगोन में भारतीय दूतावास के सहयोग से "भारत द्वारा उत्पादित वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई।

भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी के दौरान वर्ष 2004 में म्यांमार उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ ओर भारतीय उद्योग महासंघ के बीच एक संयुक्त कार्य दल के गठन के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसी तरह म्यांमार - भारत व्यापार क्लब एवं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्योग एवं वाणिज्य संघ के साथ भी आपसी समझौते किया गया। वर्ष - 2003 में गठित संयुक्त व्यापार समिति के जरिये भारत - म्यांमार के बीच वाणिज्य संबंधों का नियमन (किलेबंदी) किया गया गई। इस संयुक्त व्यापार समिति ने दोनों के बीच तेजी ले बढ़ते वाणिज्य संबंधों का दिशा - निर्देश किया है। इसके दिशा - निर्देश में दोनों देशों ने यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया एवं म्यांमार फारेन ट्रेड बैंक" तथा म्यांमार इन्व्स्टमेंट एंड कमीशन बैंक भी शामिल है। इस व्यवथा से सीमा व्यापार एवं द्विपक्षीय व्यापार में भारी बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर 2009 में भारत - म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति के तीसरी बैठक में, सीमा व्यापार को आम व्यापारिक गतिविधि में बद्दुस का निर्णय लिया गया जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जा सके।

भारत के लिए म्यांमार, एशियान देशों तक पहुंचने का द्वारा है। क्योंकि यही एक एशियन देश है जिसकी जमीन एवं

समुंद्र की सीमाए भारत से जुडी हुई है। भारत एवं एशियान देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद दोनों हिस्सेदारों के बीच व्यापार में बढ़ोतरी आवश्यक है। भारत एवं म्यांमार के बीच द्विपक्षीय निवेश बढ़ाओ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है जिससे दोनों देशों में आवाजाही में बढ़ोतरी होगी। दोनों देशों ने दो बार कर लगने पर रोक के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है जिसके मरहट सिर्फ जिस देश की कम्पनी पर भी हस्ताक्षर किया है जिसके मातहत सिर्फ देश दी कंपनी है उसे एक देश में ही उसके व्यापारिक लाभ पर उसे कर देना होगा।

दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय आपसी यात्राओं तथा " बिस्स्टेक " एवं " सार्क " जैसे क्षेत्रीय संस्थाओं में नजदीकी हिस्सेदारी से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। हाल के दिनों देशों के उच्च स्तरीय नेताओं एवं अधिकारियों ने यात्राएं की हैं उसमे अप्रील 2008 में वरिष्ठ उप सेनापति जे०

माँग आये, भारत के उपराट्टपति मो. हामिद अंसारी की 2009 की म्यांमार यात्रा तथा हाल में वरिष्ठ सेनापति थान स्वे द्वारा जुलाई, 2010 में भारत की यात्रा शामिल है।

म्यांमार और भारत ने पिछले कुछ वर्षों से व्यापार एवं निवेश के संबंधों को मजबूत किया है। विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं जिसमें म्यांमार के व्यापार एवं वाणिज्य संस्थाओं, भारत वाणिज्य एवं व्यापार यहाँ से उतर पूर्व के व्यापारिक संगठन के साथ - साथ वर्ष 2010 में कलकता स्थित वाणिज्यिक संघ की यात्राओं से आपसी मित्रवत संबंधों को मजबूती मिली है। भारतीय वाणिज्य और व्यापार संघ की ओर से योगोन एवं मंटे में एक उतर पूर्व भारत पर एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सीमा व्यापार पर रौशनी डाली गई और भारत की ओर से 52 सदस्यों के मजबूत प्रतिनिधिमंडल ने इसमें हिस्सा लिया।

बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के चलते दोनों देशों के निजी उधमियों के ढेरो पत्र प्राप्त हो रहे हैं। म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास में व्यापारिक गतिविधियों के बारे में म्यांमार ओर भारतीय उधमियों के ढेरो पत्र प्राप्त हो रहे हैं। म्यांमार के कीमती पत्थरों तथा आभूषणों और दवा क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिनिधि भारत में लगाये जाने वाले प्रदर्शनियों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वाणिज्य दूतावास भारतीय एवं स्थानीय व्यापारिक संगठनों देने का काम कर रहा है।

अल्प - विकसीत देशों के लिए कर मुक्त योजना :

दिसम्बर, 2005 के हाँगकाँग मंत्री स्तरीय घोषणा के अनुरूप भारत ने अल्पविकसीत देशों के लिये कर युक्त योजना को लागू कर दिया है।

2. योजना की सुविधाएँ :

(i) **कर युक्त सामग्रियाँ** - भारत में आयतित 85% प्रतिशत सामग्रियों पर लगाने वाली तटकर 5 वर्ष तक समाप्त काज दिए जायेंगे। इस सिलसिले में हर वर्ष 20% की घटोतरी होगी। अगस्त, 2008 से 2009 तक दो घटोतरियाँ हो चुकी हैं।

(ii) **सकारात्मक सूची** - 85% कर में मुक्ति के साथ उन सामग्रियों पर जो 9% लार देते हैं उन्हें बाजार तक पहुचने के लिए अतिरिक्त सुवोधाएँ दी जाएगी। बाजार तक पहुचने की सुविधाएँ 10% सामग्री से लेकर 100% तक हो सकती है और यह सुविधा, आयात की तारीख पर जो कर लगता उसके आधार पर दी जायेगी।

(iii) **सूची से बहार की सामग्री** - यह तटकर लगाने वाली सामग्रियों का मात्र 6% है जिसके लिए तटकर से अलग करने की सुविधा हासिल नहीं है।

3. यह योजना अल्पविकसित देशों के तमाम वैशिवक निर्यातों के 92.5% सामग्री को सुविधाएँ हासिल हैं। अफ्रीका के तत्कालिक हितों से जुड़े उत्पाद जैसे रुई, कोकोआ, अल्युमिनयम अयस्क, तांबा अयस्क, काजू, ईख से तैयार चीनी, तैयार कपडे, मछली को बहार जाने वाला वर्तन तथा गैर औधोगिक हीरे इसमें शामिल हैं।

4. इस योजना का लाभ पाने के लिये अल्पविकसित देशों को इन नशों से निर्यात होने वाले सामानों की सूची भारत सरकार को सुपूर्द करनी चाहिये तथा उन अधिकारियों की सूची भी पेश करनी चाहिये जो उन वस्तुओं के मूल स्थान के बारे में प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। यह योजना सभी अल्पविकसित देशों जिसमें 33 अफ्रीकी देश शामिल हैं, के लिये खुली हुई है।

वर्ष 2000 से विशिष्ट अतिथियों की यात्राएँ

वर्ष 2000 से दोनों देशों के उच्च स्तरिय प्रतिनिधि मंडलों का अवागमन होता रहा है जनवरी, 2000 में वरिष्ठ उप सेनापति जे. माग शिलांग से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद भारत की सप्ताह भर की यात्रा की। भारत के उप - राष्ट्रपति भेरोसिंह शेखवत ने 2 से 6 नवम्बर वर्ष 2003 में म्यांमार की यात्रा की।

राजीव गाँधी द्वारा 1987 में म्यांमार की यात्रा के बाद यह किसी भी विशिष्ट अतिथि की पहली म्यांमार यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए म्यांमार के प्रधान जेनरल थान स्वे भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वर्ष 2004 में बिदेश उद्योग उर्जा रेल परिवहन संचार विज्ञान एवं तकनीक स्वास्थ्य एवं धार्मिक मामलों के साथ 24 से 26 अक्टूबर 2004 तक भारत की ऐतिहासिक यात्रा की इस यात्रा के दौरान गैर परंपरागत सुरक्षा मुछो और म्यांमार के चिन्दिन नदी के ऊपर तमान्यी जलविधुत परियोजना के बारे में दो समझौता पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों ने आधारभूत संरचनाओं के बिकाश एवम उर्जा क्षेत्र में सहयोग के बारे में गहरी रूचि दिखाई राष्ट्रपति ए.पि.जे. अब्दुल कलाम ने म्यांमार के राज्य शांति एवम बिकाश परिषद के प्रधान सेनापति जे थान स्वे के निमंत्रण पर वर्ष 2006 में 8 से 11 मार्च तक म्यांमार की यात्रा की। भारत ने यागोन स्थित दूर संवेदी सुचना प्राप्ति केन्द्र को उच्च स्तरीय बनाने के लिए 3

मिलियन अमरीकी डॉलर सहायता के घोषणा की इसके साथ-साथ कलादान बहुदेशीय परिवहन परियोजना में म्यांमार के अंशदान

को सुनिश्चित करने के लिये 10 मिलियन अमरीकी डालर तथा 20 मिलियन अमरीकी डालर भारी करो वाले जल पंपों की खरीद के लिये ऋण मुहैया करने की घोषणा की गई। राजकीय शान्ति एवम विकाश परिषद के वरिष्ठ उप सेनापति मांग आर ने वर्ष 2008 में भारत के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान (1) कलादान नदी पर बहुउद्देशीय परिवहन परियोजना के निर्माण एवम उसे चालू करने के ढंचे पर समझौता (2) गुप्त सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा दो बार कर लगाने की प्रणाली को समाप्त करने के सवाल पर समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। म्यांमार के प्रधानमंत्री श्येन स्मैन ने दिल्ली में आयोजित " बिस्स्टेक " संगठन के प्रधानों की बैठक में शिरकत की।

11 दिसम्बर, 2010 को भारत के विदेश मंत्री एस. एस. कृष्णा के नेतृत्व में ने-पेई-राव में आयोजित 12 वां मंत्री स्तरीय बैठक में एक प्रतिनिधि-मंडल शामिल हुआ। भारत के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर म्यांमार

राजकीय शांति एव विकाश परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ जे. थान स्वे ने भारत कि राजकीय यात्रा की यात्रा के दौरान निम्लिखित दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये गये (i) अपराधिक मामलो में सहायता (ii) छोटे विकास से जुड़े योजनाओं के लिये भारत द्वारा आर्थिक सहायता पर समझौता (iii) सूचना के आदान-प्रदान तथा म्यांमार, सिन्धु बंगाल में अन्नदा मंदिर के उद्धार के कार्य १ दूर संचार, रेलवे, स्वास्थ्य और कृषी के बारे में घोषणा की गई, दिल्ली में राजनेतिक वार्ता के बाद प्रतिनिधिमंडल ने हेदराबाद, जमशेदपुर का दौरा किया जहां उन्होंने जैव तकनीक सूचना तकनीक तथा ऑटो मोबाइल उद्योगों को देखा, जनवरी, 20 से 22, 2011 को ने-पेई-रुख में आयोजित 13 वें विस्तेक मंत्री स्तरीय बैठक में शिरकत करने के लिय भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भारत की बिदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रीतम कौर नर किया,

म्यांमार में भारत की बड़ी परियोजनाएं

भारत की सरकार म्यांमार में दर्जनों आधारभूत संरचनाओं एवं गैर-आधारभूत संरचनाओं एवं गौर आधारभूत संरचनाओं से जुड़े परियोजनाओं के कार्य में सक्रिय भागीदार बन कर रही है। इन परियोजनाओं में 160 कि.मी. तामु कलेवा कलेमेयो पथ को स्तरीय बनाने तथा ही टी डिम एवं ही-फालम पथ का निर्माण एवं स्तरीय बनाना शामिल है इसके साथ कलादान बहुदेशीय परियोजना भी शामिल है टी.सी.आई.एल0 द्वारा म्यांमार के 32 भाहरों में उच्च गति वाला आंकड़ा इकट्ठा करने वाला तंत्र की स्थापना की गई है। तेल एवं गैस निगम, विदे"1 लिमिटेड, गेल एवं इस्सार कम्पनियों म्यांमार के ऊर्जा क्षेत्र में हिस्सेदार हैं। राइट्स म्यांमार के रेलवे परिवहन के विकास तथा रेलवे डिब्बों, इंजनों एवं पार्ट-पुर्जों की आपूर्ति करता है।

वर्ष 2008 के सितम्बर महीने में चिन्दविन नदी घाटी में तामन्थी एवं भवीजे जेल विद्युत परियोजना के विकास के लिए म्यांमार के विद्युत मंत्रालय, पावर-और राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के साथ समझौता हुआ। एन0एच0पी0सी0 प्रत्यक्ष भागीदारी की तैयारी कर रहा है। टाटा मोटर्स द्वारा म्यांमार में भरी टर्बो-ट्रक को जोड़ने का एक कारखाना खड़ा किया जा रहा है। भारत सरकार के आर्थिक सहायता का उद्घाटन 31 दिसम्बर, 2010 को किया गया। भारत-म्यांमार औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एच0एम0टी0 (1) द्वारा की गई है। इसके लिए भारत सरकार ने आर्थिक सहायता दी है। म्यांमार-भारत अंग्रेजी प्रशिक्षण केन्द्र, म्यांमार-भारत उद्यमी विकास केन्द्र, भारत-म्यांमार, सूचना तकनीकी क्षमता विकास केन्द्र कार्यरत हैं।

वाणिज्यिकी एवं आर्थिक संबंध

2009-10 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12.4 मीलीयन (1980-81) अमरीकी डॉलर से बढ़कर 1207.56 मीलीयन डॉलर (2009-10) हो गया है। भारत द्वारा म्यांमार से आयातित सामानों में कृषि उत्पादों का बर्चस्व रहता है। भारत द्वारा म्यांमार से आयातों में 90 प्रतिशत बीन, दालों तथा जंगल आधारित उत्पाद होते हैं। भारत के प्रमुख निर्यात में प्राथमिक एवं अर्द्ध-निर्मित स्टील एवं दवाएँ होती हैं। यागोन के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के मुताबिक निर्यात-आयात के आंकड़ निम्नलिखित हैं।

म्यांमार : भारत के साथ व्यापार

आयात	अमरीकी डॉलर		
2004-05	341.40	83.37	424.77
2005-06	489.10	80.07	569.17
2006-07	733.59	159.54	893.13
2007-08	727.85	173.46	901.31
2008-09	8004.96	146.18	951.14
2009-10	1010.56	194.03	1204.59
2010-11	551.83 (अप्रैल-अक्टुबर)	88.00	63.83

संस्थागत स्तर पर भारतीय उद्योग संघ तथा म्यांमार वाणिज्य एवं उद्योग संघ के बीच वर्ष 2000 में आपसी सहमति हुई। वर्ष 2001 में भारतीय उद्योग महासंघ एवं म्यांमार कम्प्यूटर संघ के बीच आपसी सहमति पर हस्ताक्षर हुए। भारतीय उद्योग महासंघ एवं म्यांमार उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ के बीच एवं कार्य दल गठित करने पर आपसी सहमति पर हस्ताक्षर हुए। इसी तरह भारत-वर्मा व्यापार क्लब एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र के उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ के साथ आपसी सहमति पर हस्ताक्षर हुए। वर्ष 2008 में भारत और म्यांमार के बीच तीसरे संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में युनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया के म्यांमार के तीन राष्ट्रीय बैंकों म्यांमार फॉरेड ट्रेड बैंक, म्यांनमा इकोनोमिक बैंक तथा म्यांनमा इनवेस्टमेंट एण्ड कमर्शियल बैंक के साथ आपसी सहमति पत्र पर समझौता किया। जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। वस्तुतः इस रास्ते का उपयोग सिर्फ सीमा के लिए किया जा रहा है। इसके अलावे वर्ष 2008 में दो जगह कर लगाने के प्रावधानों से मुक्ति तथा द्विपक्षीय निवेश बढ़ाओ समझौता पर हस्ताक्षर हुए। अगस्त 2009 में हुए भारत-एशियन वस्तुओं के व्यापार समझौते पर भारत-म्यांमार में भी हस्ताक्षर किये हैं।

अल्पविकसित देशों के साथ तटकर समाप्ति की योजना का लाभ म्यांमार को भी हासिल है।

सीमा-व्यापार

भारत और म्यांमार ने 1994 में सीमा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत-म्यांमार के बीच 1664 किमी सीमा रेखा पर दो स्थान मोरेह-तापू और जोखादार ही व्यापारिक कार्यों के लिए निर्दिष्ट किये गये हैं। एक तीसरे व्यापारिक स्थान अवाखुंग-पनसट/सोमरा को नियत करने पर समझौता हो चुका है। भारत-म्यांमार के बीच आयोजित तीसरे संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में अभी तक सीमा पर व्यापार के लिए नियत स्थानों सामान्य व्यापार के लिए खोल दिया जायेगा जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाया जा सके। दोनों ओर सये इस संबंध में सूचनाएँ जारी कर दी गई है।

मुद्रा-म्यांमार-भार सीमा पर मुद्रा विनियम में कठिनाईयों के चलते द्वितीय व्यापार की स्थिति कमजोर है। बहुत बार भारतीय मुद्रा में गिरावट आ जाती है। भारतीय मुद्रा में तेज गिरावट का कारण चीन-वर्मा सीमा पर चीनी मुद्रा युआन में आई गिरावट का परिणाम होता है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सभी डॉलर खाता और उसके स्थान पर यूरो खाता का बंद करने से भारत-म्यांमार सीमा व्यापार के विकास

में क्या सहायता मिली है। हाल के दिनों में म्यांमार की सरकार ने इस बात पर सहमति जताई है कि सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ व्यापार यूरो मुद्रा के जरिये साथ ही साथ उस दे"ा की मुद्रा के जरिए होगी।

दालें – हालाँकि भारत दालों का बड़ा उत्पादक दे"ा है लेकिन अपनी जरूरतों का 50 प्रति"ात इसे बाहर आयात करना पड़ता है। इसने राष्ट्रीय कृषि सहयोग एवं विपणन संघ एवं दो अन्य संस्थाओं को दालों के आयात की जिम्मेदारी दी है। भार ने दालों के आयात को तटकर से मुक्त रखने की घोषण की गई है। भारत में दालों की माँग की सबसे ज्यादा आपूर्ति म्यांमार से होती हैं। म्यांमार अपने वै"वक आपूर्ति का 60 प्रति"ात भारत को निर्यात करता है। लेकिन भारत को म्यांमार से दालों के आयात में कठिनाई उत्पन्न हो रही है क्योंकि पड़ोसी दे"ा में निजो व्यापारियों का विपणन पर वर्चस्व है। उन्हें जब भी जानकारी होती है कि भारत सरकार दालों का आयात करने वाली है, वे उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। किमतों को रोकने एवं इसकी कमी का पूरा करने के लिए वर्मा पर निर्भर करने के अलावा भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।²

म"ालें :

भारत एवं म्यांमार के बीच म"ाले के बाजार के लिए कड़ी प्रतिस्पर्द्धा है। खासकर सब्जी एवं चटनी में मिलने वाले हल्दी आदि में। म"ाले के विपणन में भारत की ज्यादा बड़ी पकड़ है लेकिन इस क्षेत्र में म्यांमार से हाल के दिनों में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है।

भारत की हल्दी अन्तराष्ट्रीय बाजार में जब 1.350 अमरीकी डॉलर प्रति टन के हिसाब से बिक रहा था वहीं म्यांमार की हल्दी की किमत मात्र 500 अमीरीकी डॉलर प्रति टन था।

भारतीय हल्दी के ऊँचे दाम के कारण कम उत्पादन तथा स्थानीय बाजार में बड़ी माँग थीं पिछले वित वर्ष में भारत ने 34,500 टन हल्दी निर्यात किया जिसकी किमत 27.52 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। पिछले वर्ष की तुलना में यह निर्यात 20 प्रति"ात कम था। लेकिन अब भारत के लिये परिस्थिति बदली है। पिछले वर्ष उत्पादन में भारी इजाफे के चलते घरेलू बाजार में हल्दी को किमतों में स्थिरता आई है। इससे लगता है कि निर्यात बढ़ेगा और फिर से अन्तराष्ट्रीय बाजार में वर्चस्व स्थापित कर सकेगा।

चाय—म्यांमार वर्ष में 90 मीलीयन किग्रा0 चाय पैदा करता है इसका 65 प्रति"ात हिस्सा उत्तरी भान राज्य में पैदा होता है।

चाय का इस्तेमाल विभिन्न तरह के धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में होता है। राजकीय समारोहों में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।

म्यांमार में तीन तरह की चाय का उत्पादन होता है। हरी, काली औश्र 52 प्रति"ात हीह, 31 प्रति"ात काली एवं 17 प्रति"ात की चाय उत्पादनों में हिस्सेदारी है। लोकप्रिय राष्ट्रीय ना"ते में काली चाय एक आव"यक तत्व है।

म्यांमार का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमेंडल ने अम का दौरा किया और भारत से चाय के उत्पादन को बढ़ाने की तकनीक की सहायता माँगी। वे भारत के चाय उद्योग की सहायता, चाय के उत्पादन एवं गुणवत्ता

को बढ़ाने के दृष्टिकोण से माँग रहे हैं। दक्षिण भारत स्थित नीलगिरी चाय बगान ने अभी अवसर को अपने हाथ में नहीं लिया है।

कीमती पत्थरों का व्यापार

म्यांमार दनियाँ भर में कीमती पत्थरों के उत्पादक के रूप में मशहूर है। इसके पास 9 कीमती पत्थर हैं। रूबी, हीरा, नीला पत्थर (बिल्ली की आँख) पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा तथा पीलापन लिए हुए रक्तमणी इत्यादि। म्यांमार में कीमती पत्थरों के उत्पादन के तीन प्रसिद्ध स्थान हैं। माण्डले मंडल के मोगोक, भान राज्य के मांगपू तथा कचिन राज्य के फेकान्ट में। कीमती पत्थरों का व्यापार विदेशों में घन कमाने का सबसे बड़ा साधन है। म्यांमार ने 1964 से लगातार कीमती पत्थरों का प्रदर्शनी लगानी शुरू की। इन कार्यक्रमों से इसने 600 मीलीयन अमरीकी डॉलर कमाया है। भारतीय कीमती पत्थरों और आभूषण निर्यात बढ़ाओं परिशद ने भारतीय खरोदारों को इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करने का काम शुरू किया है।

भारतीय म्यांमार सीमा पर कीमती पत्थरों की तस्करी एवं बड़ा मुद्दा है। रूबी, पीले हीरे आदि अन्य कीमती पत्थर म्यांमार से तस्करी के जरिये भारत में बेच दिया जाता है। कीमती पत्थरों की आपसी एवं नकली को पहचान करने की क्षमता नहीं रहने के चलते तस्कर, भारतीय व्यापारियों को ठग लिया करते हैं।

भारतीय सरकार वर्मा-भारत सीमा पर कीमती पत्थरों की तस्करी रोकने का प्रयास कर रही है। अभी हाल में मीजोरम में कीमती पत्थरों की पहचान के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है जिसमें नौजवानों को कीमती पत्थरों के सही एवं गलत की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाता है।

नीले पदार्थों का व्यापार

भारत-म्यांमार की खुली सीमा में भारत को नीले पदार्थों के आने का सामना करना पड़ता है। सीमा पर नीले पदार्थों की तस्करी के जरिये अस्त्र-यस्त्र खरीदे जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने पिछले वर्ष वर्मा की सीमा से अन्तराष्ट्रीय बाजार में 30 करोड़ रुपये की कीमत वाला नीले दावाओं का जखीरा बरामद किया। मणीपुर, मिजोरम एवं नागालैंड में नीली दावाओं की समस्या का प्रधान श्रोत म्यांमार है। दोनों देशों की जड़ी सीमाओं पर नीली दावाओं की तस्करी रोकने के लिए बहुत से समझौते हुए हैं। हाल में भारत ने मीजोरम एवं म्यांमार के बीच 440 किमी लम्बे सीमा पर लोहे की बाड़ लगाने की घोषणा की है। इसने मणीपुर के मोरेह के पास 14 किलोमीटर सीमा रेखा को भी घेरने की घोषणा की गई है।

व्यापार मेला एवं वियणन प्रोत्साहन

वर्ष 2011 में फर्मा एक्ससिल एवं म्यांमार मेडिकल एसोसियेशन के तत्वाधन में यागोन में मेला लगा। उत्तर पूर्व भारत का विहार 2010 के सितंबर महीने में माण्डले में लगा। भारतीय चेम्बर ऑफ बायर्स एवं म्यांमार चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड ट्रेड ले कलकता एवं मुम्बई का दौरा किया।

आईटीसी कॉलेजों के अन्तर्गत टीसीएस, जीएसएस एवं एमजीएसएस के अन्तर्गत म्यांमार के लोगों को प्रशिक्षण का लाभ मिल रहा है। म्यांमार के प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नलिखित है। आईटीसी – 140, एमजीसीएसएस-101 इसका उपयोग बहुत अच्छा रहा है। भारत ने 25 पत्रकारों को भी प्रशिक्षण दिया है।

सांस्कृतिक विनिमय

1997 से भारतीय सांस्कृतिक समूहों द्वारा लगातार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। दोनों देशों के विभिन्न सांस्कृतिक समूहों ने दोनों देशों का दौरा किया है। नवम्बर, 2009 में म्यांमार के छात्र प्रतिनिधिमण्डल ने सार्क सांस्कृतिक मेले में हिस्सा लिया। दिसम्बर, 2009 में वर्मा के एक लोकप्रिय बैंड "इन्पटर" ने भारत का दौरा किया और दक्षिण एशिया बण्ड मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने गीलांग एवं मेघालय में भी कार्यक्रम में भी कार्यक्रम पेश किये।

जनवरी, 2010 में भारतीय दूतावास ने भारतीय फिल्म मेले का आयोजन यागोन में किया। यागोन का यह वार्षिक फिल्म मेले एक यादगार दिन हो गया। मार्च, 2010 में वर्मा के एक प्रसिद्ध कलाकर ने एशियन कलाकर कैम्प में हिस्से लिया जो आईसीसीआर एवं एसईओचई आर द्वारा आयोजित किया गया। इस कैम्प में जो पेंटिंग बनाई गई दूतावास के सभागत में दिखाया गया जिसे सभी लोगों ने सम्मानित किया। म्यांमार से 15 सदस्यीय थियेटर समूह ने भारत में आयोजित एशियन थियेटर मेले में हिस्सा लिया। भारत के साबरी बंधुओं ने यागोन में कबूली गया। भारत नाट्यम और योग की कक्षा दूतावास में दिसम्बर, 2010 से ही लगायी जा रही है।

भारतीय प्रवासी

म्यांमार में भारतीय मूल के लोगों का उदय 19वीं सदी के मध्य में खोजा जा सकता है जबकि बर्मा के निचले भाग पर 1852 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया।

म्यांमार के दो नगरों यागोन (जो पहले रंगून कहलाता था) और माण्डले में भारतीयों की वर्चस्ववादी उपस्थिति थी। नागरिक सेवाओं, शिक्षा, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में इनका व्यापक दबदबा था। 1983 की सरकारी जनगणना के मुताबिक प्रवासी भारतीयों की संख्या 428, 428 है और राज्य विहीन प्रवासी भारतीयों की संख्या 250,000 है। भारतीय समुदाय का बड़ा हिस्सा करीब 150,000 बागो, मॉन और टेनीथारी में रहते हैं। प्रवासी परिवार यागोन में रहते हैं तथा वे निर्यात-आयात व्यापार से जुड़े हुए हैं। वे बहुराष्ट्रीय निगमों में काम करते हैं जो भारत, भारतीय दूतावास, टूरिस्ट, व्यापार, मेडिकल, अध्ययन, प्रशिक्षण, कहीं बाहर जाने के क्रम में रुकने तथा अन्दर आने का वीसा निर्गत करते हैं।³

भारत के साथ वायु, सम्पर्क सुविधाजनक यात्रा के रास्ते।

1. थाई एयरवेज के जहाज भारत के विभिन्न भाहरों तक बैंकाक के रास्ते आते हैं।
2. भारतीय एअर लाइन्स के जहाज कलकता यागोन (आना-जाना) के बीच सप्ताह में दो बार जाते-आते हैं। यह उड़ान सोमवार और भुक्रवार को होता है।

भारत और म्यांमार के बीच क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय संदर्भ में सहयोग –

एशिया-म्यांमार जुलाई, 1997 में एशियासन का सदस्य हो गया। यह अकेला एशिया दे" है जो भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़ा हुआ है। सहयोग के कुछ प्रस्तावों को लागू किया गया है और कुछ एशिया के ढाँचे के अन्तर्गत बातचीत हो रही है।

बिस्सटेक— दिसम्बर, 1947 में म्यांमार ने "बिस्सटेक" की सदस्यता ग्रहण की। म्यांमार "बिस्सटेक" द्वारा पारित स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दे" है। म्यांमार बिस्सटेक क्षेत्र में थाइलैंड और भारत के साथ व्यापार करता है। म्यांमार भारत को कृषि, उत्पादों एवं जंगल के उत्पादों का निर्यात करता है। वह भारत से रासायनिक उत्पाद, दवाएँ, विद्युत उपकरण एवं परिवहन उपकरण आयात करता है। 13वाँ बिस्सटेक मंत्री स्तरीय बैठक जनवरी, 2011 में म्यांमार में हुई।⁴

मेकॉग-गंगा सहयोग

म्यांमार मेकॉग-गंगा सहयोग की स्थापना काल नवंबर 2000 से ही सदस्य है। यह छः दे"ों की पहल से स्थापित किया गया है। इसमें भारत, म्यांमार के अलावे कम्बोडिया, लाओस, थाइलैंड एवं वियतनाम शामिल हैं। इन दे"ों के बीच यात्राओं, शिक्षा, संस्कृति, परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों में सहयोग होगा। इस संस्था का अध्यक्ष पद दे"ों के नाम के अक्षर के आधार पर तय किया जाता है।⁵

सार्क— म्यांमार को अगस्त, 2008 में पर्यवेक्षक की हैसियत से प्रवे"ा मिला। भारत एवं म्यांमार क दे"ों के बीच सीमा व्यापार बढ़ाने के लिये बहुत सी पहल हो रही है। भारत ने दोनों दे"ों में कर लगाने के प्रावधान को खत्म करने के प्रस्तावित समझौते पर सहमति दे दी है। जब यह समझौता लागू हो जायेगा तो निवे"ा बढ़ेगा। भारत से तकनीकी एवं लोगों का आना-जाना बढ़ जायेगा। इससे कर की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा तथा दोनों दे"ों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।⁶

भारत सरकार ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मणीपुर व्यापारिक स्थान के मोरेह को म्यांमार स्थित तामू स्थान पर इकोनोमिक बैंक से जोड़ने की सहमति दे दी है। दोनों बैंक ऋण पत्रों की सहूलियता का इस्तेमाल करेंगे। इसके अन्तर्गत भारतीय रुपये एवं बर्मी क्याट वैधानिक तौर पर इन बैंकों में विदे"ी मुद्रा में बदले जा सकेंगे।

बैंकिंग सहूलियतों को आसान बनाने के लिये दोनों बैंक टेलीफोन से जुड़े रहेंगे। भारत सरकार दोनों बैंकों को हॉट लाईन से जोड़ने का प्रयास करेगी। जब ये सहूलियतें भुरू हो जाएँगी तो रूपय का आदान-प्रदान बहुत आसान हो जायेगा और व्यापार अपने आप बढ़ जायेगा।

व्यापार के लायक वस्तुओं की सूची भी बढ़ जायेगा। अभी तक यह 22 वस्तुएँ ही हैं। नई दिल्ली इस सूची में जीवन-रक्षक दवाएँ, साइकिल के कल-पुर्जे, खाद, श्रृंगार प्रसाधन, कपड़े मोटर साइकिल के पुंज, एक्स-रे पेपर जोड़ना चाहती है।

म्यांमार के लोगों को स्वतंत्र रूप से मोरेह भाहर तक आने देने की योजना है। मणीपुर सरकार ने मोरेह भाहर तक आने देने की योजना है। मणीपुर सरकार ने मोरेह भाहर की आधार-भूत संरचनाओं के विकास के लिये केन्द्र सरकार के पास 200 करोड़ रुपये की योजना भेजी है। इसके जरिये एक सुगठित जाँच स्थान भी बनाया जायेगा।⁷

अन्ततः भारत के बहुत लोग यह नहीं जानते हैं कि म्यांमार क्या उत्पादन करता है और उन उत्पादों का अधिकारिक रूप से व्यापार किया जा सकता है। दो व्यापारिक हिस्सेदारों के बीच मजबूत संचार व्यवस्था का होना द्विपक्षीय व्यापार के विकास के लिये आव"यक है। इन दोनों दे"ों के बीच व्यापार प्रोत्साहन अभियान से जागरूकता बढ़ेगी। व्यापारिक समुदाय नेतृत्व लेकर व्यापार की मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे।

सन्दर्भ :-

1. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू सीबीई, गोभ, इन।
2. एचटीपी/एमईए इण्डिया एनआईसी, इन।
3. भारत म्यांमार व्यापार संबंध सैयद अली मुज्जबा पीच एचडी-7/23/2 बाय डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ग्लोबल पालिटिियन कॉम।
4. फ़ैजल याहया, विस्फोटक एवं एियन क्षेत्रीय एवं अन्तर क्षेत्रीय सहयोद के उदय के रूप, आस्टेलियन जर्नल ऑफ पोलिटिकल साइंस।
5. S.D. Muni, Expending SAARC in world Focus, New Delhi.
6. B.A. Prasad, India's Rule in the Future of SAARC, in Strategic Analysis, Delhi.

